

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून: दिनांक 26 अगस्त, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण हेतु धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के पत्र सं० आर०डब्ल्यू०/जी-23012/1/2007-डब्ल्यू० एण्ड ए० दिनांक 01.05.2007, दिनांक 21.05.2007 तथा दिनांक 21.05.2007 एवं आपके पत्र संख्या-3146/58 बजट(रा०मा०-अनु०-आयोजनेत्तर)/07-08 दिनांक 27.07.2007 के सन्दर्भ तथा शासनादेश संख्या 404/11(3)07- 122(NH)05 दिनांक 13.07.2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत रुपये 625.80 लाख के विरुद्ध उक्त शासनादेश के द्वारा अवमुक्त रुपये 256.67 लाख के पश्चात अवशेष धनराशि रुपये 369.13 लाख (रुपये तीन करोड़, उन्हत्तर लाख, तेरह हजार मात्र) की धनराशि राज्य सरकार के बजट से निम्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र०सं०	मद	धनराशि (लाख रुपये में)
1.	सामान्य मरम्मत (ओ०आर०)	369.13
	योग	369.13

- व्यय उसी कार्य पर किया जाय, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, नियम तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की दैनिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का मदवार विवरण शासन/भारत सरकार को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा।

G. S. Mehta

5. धनराशि का व्यय करने में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और उक्त धनराशि के विपरीत भारत सरकार से अविलम्ब आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। ?
6. निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणन पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय और आगणन में ली गई रोड़ का सत्यापन अधीक्षण अभियन्ता से कराकर इसकी सूचना शासन को दी जायेगी।
7. उक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि को दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा और इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार व राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।
9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-22 के लेखा शीर्षक-3054 सड़क तथा सेतु-01 राष्ट्रीय राजमार्ग-आयोजनेतर-337 सड़क निर्माण कार्य -04 राष्ट्रीय मार्ग अनुरक्षण (100/ के0स0) (03 से स्थानान्तरित)-00-29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।
10. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अ.शा. संख्या 179/XXVII(2)/07 दिनांक 09 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

पू.सं.466 (1)/III(3)2007 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराखण्ड, इलाहाबाद/देहरादून।
- 2- अनु सचिव, पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- अपर सचिव, वित्त वजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8- सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता/अधिशाली अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- 9- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-2/गार्ड बुक।
- 11- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।